(1100/VB/PS)

(प्रश्न 61)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि देश के दूरसंचार क्षेत्रों में कार्यरत एमटीएनएल एवं बीएसएनएल टेलीफोन उपभोक्ताओं को सभी उपकरण उपलब्ध होने, योग्य एवं उच्च प्रशिक्षण प्राप्त उच्च अधिकारियों के होने के बावजूद भी अच्छी सेवा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। जबकि कम मानव शक्ति एवं कम उपकरण वाले प्राइवेट क्षेत्रों की दूरसंचार कम्पनियाँ देश की सरकारी कम्पनियों एमटीएनएल एवं बीएसएनएल को पछाड़ रही हैं। असंतोषजनक सेवा और खराब टेलीफोन सेवा के कारण लोग एमटीएनएल एवं बीएसएनएल की सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट कम्पनियों की सेवाएँ ले रहे हैं, जिससे एमटीएनएल एवं बीएसएनएल को लगातार घाटा हो रहा है और प्राइवेट कम्पनियों को लाभ मिल रहा है, जिसमें वोडाफोन और एयरटेल आदि कम्पनियाँ हैं।

ऐसी परिस्थिति में, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने एमटीएनएल एवं बीएसएनएल के उच्च अधिकारियों की वर्तमान और खराब व्यवस्था की जिम्मेदारी की समीक्षा की है? अगर हाँ, तो दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

श्री रविशंकर प्रसाद: सर, माननीय सदस्या ने एक गंभीर और बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया है। मैं सदन की समझदारी के लिए इसको थोड़ा विस्तार से समझाना चाहूँगा। एक बात मैं कहूँगा कि कॉम्पिटीशन आया है। प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं। लेकिन फिर भी, बीएसएनएल का मार्केट शेयर 31 मार्च, 2017 को 9.63 प्रतिशत था, अब 31.03.2019 को वह बढ़कर 10.72 प्रतिशत हुआ है। एमटीएनएल में थोड़ी-सी कमजोरी आई है। एक बात इस सदन को बताना बहुत जरूरी है कि बीएसएनएल के पास अधिकारी समेत 1,65,169 एम्प्लॉइज हैं। एमटीएनएल में 21,679 एम्प्लॉइज हैं। बीएसएनएल की जो एम्प्लॉई कॉस्ट है, वह इनकम का 75.06 पर्सेंट है और एमटीएनएल का 87.15 पर्सेंट है। बाकी कम्पनियों में, किसी का 2.94 पर्सेंट है, किसी का 5.59 पर्सेंट है।

हमारे पास कर्मचारी ज्यादा हैं। हमारा काम है उनकी चिन्ता करना क्योंकि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वह कश्मीर की बाढ़ हो, नेपाल का भूकम्प हो, अभी ओडिशा में जो आपदा आई, तमिलनाडु की बाढ़ हो, उनमें बीएसएनएल ही आगे बढ़कर फ्री सेवा देता है ताकि लोगों को सुविधा मिले।

अब हम क्या कर रहे हैं, मंत्री बनने के बाद मैंने स्वयं छह-सात मीटिंग्स ली हैं। मैं इनको और प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बारे में सभी संभावनाओं की तलाश कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि बीएसएनएल ने अपने समय में कई प्रकार के कार्यक्रम किये हैं, इस दिशा में और भी कार्यक्रम करने की आवश्यकता है, जिसमें मैं लगा हुआ हूँ।

(1105/PC/RC)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहूंगी कि वर्तमान समय में एमटीएनएल एवं बीएसएनएल की जो दयनीय हालत हो गई है, उसका मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया है। मैं यही जानना चाहती हूं कि जो परिस्थिति है, वह उसको वॉच करने की है या उसके मूल कारणों का पता लगाने की है? वह पता नहीं लग पा रहा है। हम मीटिंग बुलाते हैं या आप जो मीटिंग बुलाते हैं, उसमें इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। जैसे एक कमेटी बनाई जाती थी और कमेटी में निर्देश दिया जाता था कि ये-ये दिक्कतें आ रही हैं, उनमें सुधार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। वह मीटिंग कभी छ: महीने में या एक साल में बुलाते हैं, लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं निकलता। जो आदमी क्वेश्चन उठाता है या जहां से भी विभाग को खबरें देता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वे इस तरह की कमेटियों को टाइट कर के बनाने का काम करें, जिससे हमारा और आपका नाम हो। आप बहुत मेहनत करने वाले मंत्री हैं। आपने बहुत अच्छे से जवाब लिखा है, लेकिन थोड़ी सी कमी दिख रही है। बीएसएनल और एमटीएनएल के टावर नहीं मिलते हैं, जिसके कारण लोग प्राइवेट नेटवर्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कतें होती हैं। धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, श्रद्धामना रमा देवी जी का सुझाव एक एक्शन के लिए है। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और इनवॉल्वमेंट हो, ताकि उनके सुझावों पर हम और प्रभावी रूप से विकास के कार्य कर सकें।

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या एमटीएनएल और बीएसएनएल ने अपनी इक्विटी के एवज में 4जी स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए सरकार से गुज़ारिश की है? आने वाले दिनों में 5जी और 6जी का पूरे विश्व में जाल फैलेगा, तब एमटीएनएल और बीएसएनएल इसके साथ कम्पीट कर सकें और अच्छे तरीके से ग्राहकों को सेवा प्रदान कर सकें, जिससे सरकार की ये दोनों कंपनियां अच्छे मुनाफे तक जाएं। मंत्री जी ने मार्केट शेयर बढ़ा है, यह तो बताया, लेकिन टोटल मार्केट शेयर कितना बढ़ा है और उसमें इन दोनों कंपनियों का क्या प्रतिशत है, यह भी मंत्री जी बताएं। धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, हमें एक बात समझनी चाहिए। इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां बहुत आई हैं। इससे कॉम्पटिशन भी होता है, प्रतिस्पर्धा होती है और कुछ डिसर्पशंस भी होते हैं, लेकिन इसका जनता को फायदा भी मिलता है। आज भारत में मोबाइल रेट और डेटा रेट दुनिया में लोएस्ट है, यह हमें समझना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वह कॉम्पटिशन फेयर होना चाहिए।

माननीय सदस्य ने 4जी की बात कही है। पूर्व में एक विचार हुआ था, चूंकि बीएसएनएल और एमटीएनएल सरकारी पीएसयूज़ हैं, अगर हम इनको स्पैक्ट्रम के ऑक्शन में भाग नहीं लेने देंगे, तो संभवत: लगेगा कि सरकार इनके पीछे खड़ी है। हां, माननीय सदस्य का एक बहुत ही उचित विचार है कि 4जी की उपलब्धता इन दोनों कंपनियों को हो। मैं इसके बारे में पूरी संभावना तलाशूंगा।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Speaker, Sir, I express my thanks for giving me the chance to put this supplementary question.

Data is there and I am not disputing that data at all. But the point remains somewhere else. Today even in the rural areas, there would be net banking, and net system. There is a need for providing access to the net. Today, in the rural areas or anywhere else including cities, 3G is not sufficient for any net banking and net system and there is a need for 4G. Will you wait for the things to improve or, you will do something about it?

The intention of the Government is to make digital India. It is very good and we appreciate it. But for making an effective digital India, you have to improve the quality of towers and you require enhancement up to 4G. I have a very specific question to ask from the hon. Minister. Are we in a position to enhance it up to 4G? Are we in a position to improve the efficiency of mobile towers? Everybody has his experience about it. I think all the MPs would want to speak about it. We had raised this matter in the Committee of 16th Lok Sabha. With the MTNL telephone which has been given to us, we do not get anything.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Hon. Speaker, Sir, the question which hon. Kalyan Babu has asked has two components. The first component is whether we are improving towers and network system. The answer is, 'yes' and 50,000 towers have been installed. If I can give you very specific numbers, in the last five years itself, the number of BTS installed by BSNL is 25200 and total BTS working in the country including BSNL and MTNL are 20 lakhs. Therefore, this

has been done and I can give you further details of the other steps that have been taken.

Regarding availability of 4G, I would like to very humbly clarify to you that 4G gives good digital connect. That point is well taken, but as far as the banking system of India is concerned, you may recall, whether it is 2G or 3G, the banks have been operating on that. Therefore, to say that in the absence of 4G, banking system has completely got derailed is a little tall claim. But I do take your point that these public sector bodies need to be supplemented with 4G. As I said on the first day when I took over, I will explore all the options to make them viable and to make them competitive. I have also conveyed it to them and I have conveyed today to the employees of MTNL and BSNL that they also need to work together in a more professional capacity because I always feel very strongly to ensure a fair competition and to ensure equilibrium in the sector, we need to have a public sector undertaking also. When it comes to Tsunami or earthquakes or Tamil Nadu floods or when it came to recent cyclone in Odisha, it is only entities like BSNL which give free service and bring succour. This is how we have to work.

(1110/SPS/RC)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): यह बिल्कुल सही है कि बी.एस.एन.एल. जैसी कंपनियां जब भारत में होती हैं तो प्रतिस्पर्धा देती हैं, लेकिन मेरा एक सवाल माननीय मंत्री जी से पूछना उचित होगा कि जब आपदा आती है तो सिर्फ बी.एस.एन.एल. लगती है और बाकी कंपनियां ध्यान नहीं देती हैं। यह उचित नहीं होगा क्योंकि जब हजार मिलियन सबस्क्राइबर्स हैं तो सबके टावर्स होते हैं, सब चलते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा और कोटेक इक्विटी की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बी.एस.एन.एल. का जो घाटा है, लगभग 90 हजार करोड़ है। यह उसी प्रकार से है, जैसे एयर इण्डिया का है। यह हमारी कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है। हमारा दायित्व बनता है इनके कर्मचारियों को बचाना और इसको प्रॉफिट में लाना। महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अभी जवाब दिया है और इनके ही बी.एस.एन.एल. की बैलेंस शीट है, इन्होंने कहा है कि कंज्यूमर्स का प्रतिशत बढ़ा है। इन्होंने कहा है कि वह 9 प्रतिशत से 10 प्रतिशत हो गया है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि वर्ष 2017 में इनकी आय 3 लाख 153 हजार करोड़ थी और जब 1 प्रतिशत बढ़ गया है तो इनकी वर्ष 2018 में 31 मार्च तक आय 1 लाख करोड़ कम हो गई, जो 2 लाख 507 करोड़ हो गई है। अगर इस प्रकार के आंकड़े पब्लिक डोमेन में हों और हम फिर भी उसके बाद यह कहते रहें, आज भी हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, वह बी.एस.एन.एल. का करते हैं, पार्लियामेंट के सभी सदस्य। हमारा कमिटमेंट है। जब कोई टेलीफोन नहीं था तो बड़े-बड़े सेट इसी पार्लियामेंट में 1996 में दिये गए थे, जो बी.एस.एन.एल. के थे। आज भी हम लोग लॉयल हैं, लेकिन हमारे लिए कठिनाई है कि जब हम फोन करते हैं और फोन कटता है तो उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। जब उधर से बिलिंग होती रहती है तो देश में सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। हर आदमी जिसके पास बी.एस.एन.एल. है, वह सरकार पर अंगुली उठाता है, जब वह उस फोन को उपयोग करता है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। महोदय यह विषय बहुत बड़ा है। जिस प्रकार से एयर इण्डिया का संकट पूरे भारतवर्ष में है और हम अपना पैसा, सरकार का खजाना लगाकर चला रहे हैं उसी प्रकार से बी.एस.एन.एल. को भी सरकार का खजाना लगाकर चला रहे हैं। यह कब तक चलता रहेगा? माननीय मंत्री जी इसका दूरगामी रास्ता क्या होगा, उसके बारे अगर टिप्पणी करना चाहें तो कीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आरम्भ में ही कहा कि इस विभाग के एक महीने पूर्व मंत्री बनने के साथ ही मैंने कहा था कि इसकी और तेज गति हो, इस कंपनी का स्वास्थ्य बढ़े। इसके लिए मैं सारी संभावनाओं की तलाश करूंगा और तलाश हो रही है। आपने जो एक बात

बैलेंस शीट की कही, उसको मैं स्वयं एग्जामिन करूंगा और उसके बारे में टिप्पणी करुंगा। माननीय रूडी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस विभाग को मैंने पहले भी देखा था। कई बार प्राइवेट कंपनियां नेचुरल कैलामिटी में दो दिन के लिए फ्री करती हैं और बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल. जब तक कैलामिटी खत्म नहीं होती है तब तक फ्री करती है। इस दृष्टिकोण से मैंने कहा था। इसलिए यह देशहित में है कि यह कंपनियां स्वस्थ हों।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): माननीय अध्यक्ष जी, शुक्रिया जो आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। मेरा स्पेसिफिक सवाल मंत्री जी से है कि हमारे बॉर्डर इलाकों में आपकी यह सुविधा बहुत कमजोर है। हमारे लोग और जो वहां फौजी हैं, वे घर से बात नहीं कर सकते हैं। श्रीनगर के आपके केन्द्र में मशीनें पड़ी हुई हैं, मगर उनको लिफ्ट करने के लिए बड़ा हेलीकॉप्टर चाहिए, जो एयरफोर्स से चाहिए। अगर यह सुविधा इनको मिल जाएगी तो इन मशीनों को वहां तक पहुंचा सकेंगे और हमारे बॉर्डर इलाकों में आपके बी.एस.एन.एल. की सुविधा ठीक हो जाएगी। उसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। शुक्रिया।

(1115/KDS/SNB)

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): आपने श्रीनगर की जो स्पेसिफ़िक समस्या बताई है, उसको मैं स्वयं देखूँगा, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हमारी सेना के जवान, जो बॉर्डर पर हैं, वह अपने परिवार से बात कर सकें, इसके लिए बीएसएनएल ने कई कार्यक्रम चलाए हैं। मैं इसकी स्वयं समीक्षा करूँगा कि इसको और मजबूत किया जाए। श्रीनगर का विषय मैं स्वयं देखूँगा।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती संगीता आजाद।

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 17वीं लोक सभा में प्रथम बार बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को भी धन्यवाद देती हूँ और हमारे क्षेत्र लालगंज की जनता की भी बहुत-बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुझे यहाँ भेजा

है। माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में बी.एस.एन.एल. की कुल कितनी लैण्डलाइन व मोबाइल कनेक्शन वर्तमान में उपलबध हैं? यदि इन कनेक्शनों में लगातार गिरावट हुई है तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में बी.एस.एन.एल. को अपना वज़ूद कायम रखने के लिए कौन-कौन से सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि किन कारणों के चलते बी.एस.एन.एन. की सेवाएँ शाम होने के बाद से ही बाधित हो जाती हैं? कहीं इनकी सेवाओं को बाधित करने के लिए दूसरी निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाने का मकसद तो नहीं है? धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने आज़मगढ़ जिले के बारे में एक संख्या जानने की बात कही है, जो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। आज़मगढ़ में कितने टावर्स हैं, कितने मोबाइल्स हैं, उनका डिटेल लेकर मैं आपको जरूर भेज दूँगा, लेकिन जहाँ तक आपने बाकी गुणवत्ता की कमी का सवाल किया है, उसका मैंने विस्तार से उत्तर अवश्य दिया है। फ्री रोमिंग की सुविधाएँ हमने दी हैं, जो केबल कनेक्टिविटी कॉपर की है, उसको फाइबर से कर रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की बात है, उसमें आज एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी हो गई है, यह सारा काम सफलता से बी.एस.एन.एल. ने किया है। जो हमारे नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम, जो पूरी सेना के लिए हम काम कर रहे हैं, वह काम बी.एस.एन.एल. कर रही है। जो नक्सलाइट इलाके हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे हैं, जो पूर्व में गृह मंत्री थे, उनके उस समय के विभाग से को-ऑर्डिनेशन करके जितने लेफ्ट-विंग एक्स्ट्रीमिस्ट एरियाज़ हैं, उसमें लगभग तीन हज़ार टॉवर लगाकर इसी बी.एस.एन.एल. ने काम किया है। ऐसे कई काम हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करने की जरूरत है, लेकिन हाँ, एक प्रतिस्पर्धा का युग है, प्रतिस्पर्धा में ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा हो, यह हमारी कोशिश होगी।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रक्षा खडसे।

श्रीमती रक्षा निखिल खडसे (रावेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि अभी आपने बताया कि बी.एस.एन.एल. में सुधार हेतु सरकार के

माध्यम से काफी कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरा आपसे यह सवाल है कि प्राइवेट कंपनी को भी हम आग्रह कर सकते हैं कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में और आ.दिवासी क्षेत्रों में जाकर काम करे, क्योंकि अभी सभी योजनाएँ इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, बैंकिंग व्यवस्था इंटरनेट से जुड़ी हुई है, लेकिन यह व्यवस्था न होने के कारण आदिवासी क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दिक्कत आती है, धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, जो निजी कंपनियाँ हैं, उनका विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा, उस बात को मैंने स्वयं संज्ञान में लिया है कि कई ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं, जहाँ पर निजी कंपनियों का प्रभाव कम है। उनका सुझाव बहुत सही है। इस बात की मैं कोशिश करूँगा कि बी.एस.एन.एल. के साथ-साथ बाकी निजी कंपनियाँ भी सुदूर जंगल के क्षेत्रों में जाएँ। यहीं पर, इस सदन को यह भी जानने की जरूरत है कि बी.एस.एन.एल. और प्राइवेट कंपनियों में क्या अंतर है? बी.एस.एन.एल. आदिवासी इलाकों में कमिटमेंट के साथ जाती है, भले ही प्रॉफिट हो या नहीं हो, क्योंकि वहाँ जाना जरूरी है। यह दृष्टिकोण प्राइवेट कंपनियों का भी हो, यह हमारी कोशिश होगी।

(इति)

(Q. 62)

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Hon. Speaker Sir, thank you for giving me this opportunity.

The US Government has recently announced that it would end the privileges that India enjoys under the Generalised System of Preferences (GSP) starting from 5th June, 2019. The GSP was implemented in 1974 and it is the largest and the oldest US trade preferences scheme and it allows duty free import for thousands of products from designated countries like India.

(1120/RU/MM)

Sir, out of the total exports of 48 billion US dollars, we export worth of around 6.3 billion US dollars to US under GSP. Unfortunately, the withdrawal decision of GSP will have a reasonable impact on our exports. This action under GSP is an indicator of tough trade position by the US against India.

I think India's loss of GSP status is a diplomatic setback and not an economic setback.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to how the Government proposes to address the trade related discontent which will definitely grow into a bilateral trade dispute in the near future and how India will negotiate to restore the GSP benefits.

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Speaker Sir, it is important for the House and the people of India to know that the channelized system of preferences have been offered by the United States of America, of course, for the last almost 45 years. It may be probably, from 1975 which was also referred to yesterday. But it was

largely a non-discriminatory and unilateral concession that the United States started giving to the less developed or the least developed countries to the developing countries which, at that point of time, were in great deal of difficulty. Over a period of time, that has certainly helped India also to export more products to the United States. But as we have seen in the last few years, Indian industry is standing on its own feet, is becoming competitive and is able to compete with the rest of the world on its own terms, on the strength of its competitiveness and comparative advantages.

Today, in the overall context of things, we have an export of over 50 billion dollars to the US alone which in rupee terms comes to Rs. 4 lakh crore. The GSP that we were enjoying was being enjoyed in a very few products all of which totalled only Rs. 40,000 crore out of the larger basket of Rs. 42,000 crore.

Another thing to be noted is, even within this Rs. 42,000 crore export basket, nearly two-third of the products were getting benefit under four per cent. Our Indian industry is not so weak that they will not be able to compete on the withdrawal of GSP benefit which amounted to such a small amount.

At the outset, I would like to state that US has taken a unilateral position. We believe that it is not exactly as per the norms of WTO and GATT which have been mutually agreed and which are multilateral trade agreements. But, having said that, obviously, these are issues that come up in international trade. From time to time, countries have to engage with each other. There are always trade discussions and negotiations going on.

But one thing is very clear. This Government led by Prime Minister, Shri Narendra Modi will never ever compromise on national security and national sovereignty and at no point of time will trade negotiations be allowed to overtake what is in the national interests and the interests of the people of India.

Obviously, trade negotiations are going on. This particular step happened during the midst of the elections when obviously the Model Code of Conduct was in place and we were all, in this House also, busy with the election process. Soon after the new Government was sworn on the 30th of May, the Untied States took the decision on the 31st May to withdraw the GSP concessions from 5th June. We are in dialogue with the United States. We have a very very strong and healthy relationship with the United States of America, the world's oldest democracy. We are the world's largest democracy. Two large democracies engage with each other on very strong people-to-people ties, leader-to-leader ties and nation-to-nation ties.

I have no doubt in my mind that while going forward, the diplomatic engagement and the trade engagement with the United States will only get stronger and better in the years to come.

I can assure the entire House, through you Sir, and the people of India on this point. India engages with the United States on a number of diplomatic strategic trade issues all of which are on the basis of sovereign interests of the country. Both the countries protect their mutual trade and business interests.

(1125/NKL/SJN)

Both the countries protect their strategic interest, and given the relationship that has been developed in the last five years with the United States, we have, today, a strong strategic partnership with the United States of America.

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Speaker Sir, we also know that the US has been pressurising India to extend patent protection to chemical and pharmaceutical products by giving this olive branch of GSP. We should understand that the matters like GSP are a double-edged sword. India is already facing several cases in the WTO Dispute Settlement Body.

My second point is this. Will the hon. Minister be pleased to say as to what steps will be taken to recalibrate the approach which could enhance the competitiveness of Indian Exports and also will this subject be discussed in the upcoming meeting between the hon. Prime Minister and the President Trump on the side-lines of the G20 Meeting?

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Speaker Sir, as far as engaging with different countries on different matters of trade, patents and services is concerned, these are all matters which are mutually discussed between different Governments. The decisions are taken in national interest, protecting the overall interests of trade and business in the country. I can assure the hon. Members, through you, Sir, as I said earlier, India will always ensure that Indian industry, business and trade are protected and given due consideration when matters like these are discussed. I do not know where the hon. Member

got this information from that we are trying to trade off the GSP revival with the patent laws. There is nothing like that on the Table. I have had discussions. The Government of India is continuously in a dialogue with the United States also, and never once has this issue cropped up. So, I would urge the hon. Members not to bring in issues based on hearsay or newspaper reports, especially when they are related to very delicate issues like international negotiations and international discussions because that only serves to harm the interests of India and the interests of negotiations. While you have been in Government for many years before we came in, I am sure, you will also appreciate that any such international disputes, any such international engagement and negotiations are best left to the people in the room rather than being discussed in the open house. Having said that, Sir, the hon. Member also raised the issue of supporting export. …(*Interruptions*) I can assure the hon. Member that the Government of India, throughout the last five years, has continuously given more and more concessions, has continuously sat and worked with the exporter community to see as to how we can strengthen their competitiveness. I had very detailed discussions with different sectors of export industry over the last 25 days that we have been in Government in our second term, and since I took charge of this department, we have had extensive discussions with small traders, *Kirana* store owners, and the MSME/ industry associations, to understand as to how we can help them become more competitive. I have had discussions with bankers, financial institutions and the Export Credit Guarantee Corporation which supports

exports through insurance. All of these engagements are helping us to further improvise the methodology and the delivery of support to make Indian exports more and more competitive.

श्री दीपक बैज (बस्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि अमेरिका से आने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने के कारण क्या सस्ती दर पर भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तुएं मिलेंगी? इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है तथा जीएसपी हटाने के कारण भारतीय व्यापारियों तथा उत्पादकों पर इसका क्या असर होगा?

श्री पीयूष गोयल : महोदय, अमेरिका ने कन्सेशन विदड्रा किया है। भारत का जो निर्यात होता है, उसके ऊपर जो कन्सेशन था, उसे विदड्रा किया है। उससे भारत के उपभोक्ताओं के ऊपर वास्तव में कुछ असर पड़ने की संभावना नहीं है। भारत के अंदर जो सामान आता है, उसके साथ इस जीएसपी विदड्राल का कोई संबंध नहीं है। हमारा जो कन्जूमर डिपार्टमेंट है, जो पूरे समय प्राइजेज को मॉनीटर करता रहता है और वाणिज्य विभाग भी, ये दोनों विभाग संतुलन के साथ काम करते हैं। देश में कीमतों के ऊपर हम लगातार निगरानी करते रहते हैं। वास्तव में, इस देश में पहली बार इतनी कम महंगाई की दर बढ़ने का जो दौर देखा है, वह अपने आपमें ऐतिहासिक रहा है।

(1130/GG/KSP)

कहां हम डबल डिजिट मंहगाई, जैसे कभी 12 पर्सेंट तो कभी 14 पर्सेंट पर होते थे। सन् 1974-75 में तो मंहगाई की ग्रोथ 34 पर्सेंट हुई थी। …(व्यवधान) तो वहां से ले कर कहाँ सन् 2014 से 2019 के बीच मंहगाई की दर पांच सालों में एवरेज़ सिर्फ चार-साढ़े चार प्रतिशत के करीब रही है। …(व्यवधान) और आजकल की मंहगाई की दर तो शायद तीन प्रतिशत से भी कम हो गई है। …(व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Hon. Speaker, Sir, I heard the rather long filibustering answer which the hon. Commerce Minister gave. I would just like to tell him that this GSP situation did not manifest itself while the

Model Code of Conduct was in place. This is something which has been festering ever since President Trump took office in 2016.

My specific question to the hon. Commerce Minister is that when this had been festering since 2016 and you had a number of rounds of negotiations with the USTR, why was your Government not able to handle the situation and why did things come to such a pass that these GSPs had to be invoked.

My second question, if you would allow me, is to the hon. Prime Minister and to the Foreign Minister since they are here. The US Secretary of State Pompeo is in town today. I would like to ask the hon. Prime Minister whether he would tell the US Secretary of State, when he meets him, that this bullying and arm twisting by the United States of America will not be tolerated by India.

माननीय अध्यक्ष : आप अभी माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछिए। यह डबल क्वेश्चन हो गया।

…(व्यवधान)

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, the hon. Member has been a member of the Union Cabinet before this Government came in and I am sure he jolly well understands that when a Minister gives a detailed reply, I think the House appreciates it. If he calls it filibustering, I think it is an insult to the Member of his own Party who raised the question in the first place whom I am trying to address with a very detailed answer. Moreover, filibustering, I would like to tell the hon. Member, is done in the United States Senate and not in India.

Secondly, I do not know whether the hon. Member gets his information that the United States was considering withdrawal of GSP since 2016. I have not read any news article; I have not read any information which gave us this

clue that the United States was considering removing it since 2016. It is something which he may be privy to; maybe he has better contacts which keeps giving him information about what is happening. But I must say that if at all I was to grant the hon. Member that the United States was considering to withdraw this from 2016, I think it is only a recognition of the growing strength of India as an economy, because the GSP was originally intended, as I explained to the Member earlier, for the Least Developed Countries and for the Under Developed Countries. It had a benchmark that will only be for countries which are not in the definition of High Income Countries and, therefore, if at all the United States has started looking at India from India's position of strength as a country which is developing rapidly, particularly in the last five years, I think it is a matter of pride for all the people of India.

(ends)

(प्रश्न 63)

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): स्पीकर महोदय, बड़ा डीटेल्ड आंसर मंत्री जी ने दिया है। मैं यह भी समझता हूँ कि जो परमाणु शक्ति है, उस फील्ड में भारतवर्ष ने अपना बहुत बड़ा स्थान कायम किया है। मैं यह भी जानता हूँ कि आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, वह क्लाइमेट चेंज है। परमाणु शक्ति इसका एक सॉल्युशन है। परंतु यह भी सही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से न्यूक्लियर प्लांट्स को भी खतरा बढ़ा है। समुद्री तूफान, सुनामी, पानी के तापमान का बढ़ना आदि इन सबकी वजह से न्यूक्लियर प्लांट्स को नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत बढ़ा है। न्यूक्लियर डिज़ास्टर का रिस्क भी बहुत बढ़ा है।

(1135/GG/SRG)

उदाहरण के तौर पर सन् 2011 में जपान में फूकूशिमा न्यूक्लियर पॉवर प्लांट को भूकंप के बाद बंद करना पड़ा था। इसी तरह सन् 2014 में भारतवर्ष में कलपक्कम प्लांट को भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा था।

स्पीकर महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर पॉवर प्लांट्स से ऊर्जा बनने का जो खर्च आता है, वह बिजली के दूसरों स्त्रोतों से बहुत अधिक आता है। यह खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है, जबकि सोलर और विंड जैसे स्त्रोतों से बिजली पैदा करने की लागत लगातार कम हो रही है। मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें इन्होंने कहा है कि सोलर से एक मेगावॉट का जो खर्च आता है, वह चार से पांच करोड़ रुपये आता है और न्यूक्लियर पॉवर से जो खर्च आता है, वह 15 करोड़ रुपये आता है। मैं यह समझता हूँ कि सोलर, विंड और दूसरे स्त्रोतों से जो रोज़गार की संभावनाएं हैं, वे भी ज्यादा हैं। जो रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट है, वह भी बढ़ जाती है। साथ में जो रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं, उसको सेफली डिस्पोज़ करना भी इतना आसान नहीं है। इन्हीं कुछ कारणों से यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा और जापान जैसे देश अपने बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स डीकमीशन कर रहे हैं। एक प्लांट को डीकमीशन करने में भी कई साल लगते हैं और उस पर बहुत भारी रकम लगती है। इस ट्रेंड के उलट हम भारत में एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स स्थापित कर

रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में जब बिजली पैदा करने के अन्य स्वच्छ और सस्ते स्रोत मौज़ूद हैं तो क्या नए न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करना जस्टिफाइड है, वाज़िब है? इन सब बातों पर मैं भारत सरकार की राय जानना चाहता हूँ।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें दो-तीन प्रश्न आ गए हैं। पहला तो सेफ्टी को ले कर है। सदस्य जी का यह कहना है कि यदि उसमें कुछ सेफ्टी रिलेटेड कोई आकांक्षाएं हैं तो शायद प्लांट और लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। दूसरा, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है और तीसरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस को ले कर है।

जहां तक सेफ्टी का संबंध है, इन्होंने फूकूशिमा का उदाहरण दिया है। मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम में पूरी तरह से सेफ्टी का ध्यान रखते हुए एक मंत्र का पालन किया जाता है कि 'safety first production next', उस पर कभी कोई समझौता अथवा कम्प्रोमाइज़ नहीं रहता है। जब कोई नया प्लांट प्लान किया जाता है तो कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्लानिंग के दौरान उसका हर तीन महीने में जायज़ा लिया जाता है। फिर जब उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है, हर छह महीने बाद लिया जाता है। जब वह काम करना शुरू कर देता है तो हर पांच वर्ष के बाद और फिर दस वर्ष के बाद उसका पुन: लाइसेंस रिन्यु करने का रहता है। जहां तक सुनामी की इन्होंने बात की है, हमारे अधिकतर प्लांट्स ईस्टर्न कोस्ट और वैस्टर्न कोस्ट पर हैं। ईस्टर्न कोस्ट पर जहां बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है और सबसे नज़दीक सुनामिक ज़ोन जो वहां पड़ता है, वह इंडोनेशिया में लगभग 1500 किलोमीटर दूर पड़ता है। वह भी सेफ्टी की दृष्टि से बड़ा सिक्योर है। वैस्टर्न कोस्ट, जहां हमारे तारापुर इत्यादि के प्लांट्स है, उनका नियरेस्ट सुनामिक ज़ोन पड़ता है कराची के आगे वैस्ट पाकिस्तान में, जो पहले वैस्ट पाकिस्तान था और अब पाकिस्तान है, वह भी लगभग 900 किलोमीटर है। उस दृष्टि से हमें कोई संदेह करने

की आवश्यकता नहीं है। जहां तक कॉस्ट इफेक्टिवनेस का सवाल है, महोदय, इन्होंने ठीक कहा है कि इसमें दो बातें हैं। यह कहना शायद पूरी तरह उचित न हो कि न्यूक्लियर एनर्जी का कोई औचित्य है भी कि नहीं। क्योंकि वास्तविकता यह है कि nuclear energy is going to be the main source of energy for India's rising energy requirements in the years to come, और साथ ही साथ यह क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। यह भी इन्होंने ठीक कहा है कि उसकी लागत वर्तमान में लगभग 15 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट है, जबकि दूसरे सोर्स की लागत लगभग 5-10 करोड़ रुपये के लगभग है। अपने-अपने मैरिट्स रहते हैं। सोलर एनर्जी यद्यपि क्लीन सोर्स है, लेकिन वह स्टेबल नहीं रहता है।

(1140/KN/KKD)

इसी तरह थर्मल पावर का क्लाइमैटिक और पॉल्यूशन वाला भी एंगल है और लागत भी ज़्यादा रहती है। इसके साथ-साथ मैं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आपके माध्यम से यह भी हाउस के साथ साझा करूँ कि पिछले 4-5 वर्षों में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी गाइडेंस में अनेक ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जिससे कि हमारे एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को बल मिले, प्रोत्साहन मिले, हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास की हौसला अफजाई हो और आर्थिक सहयोग भी मिले। उदाहरण के तौर पर एक मिनट में मैं आपको यह बता दूँ, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते मंत्रिमण्डल ने यह फैसला किया है कि हर वर्ष एक नया रिएक्टर लगाया जाएगा, देश में आने वाले कुछ वर्षों के लिए, ताकि हमारे एटॉमिक एनर्जी प्लांट की एक्सपेंशन भी हो और उसकी जनरेशन भी बढ़े। पहली बार मंत्रिमंडल के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दस करोड़ रुपये प्रति वर्ष अगले दस वर्ष के लिए इस बजट में निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है ज्वाइंट वेंचर्स को लेकर। पहले चूँकि एटॉमिक एनर्जी में हमें धनराशि और बजट की दिक्कतें और दुविधाएँ रहती थीं, क्योंकि यह पूरी तरह गवर्नमेंट सेक्टर में था। अब यह निर्णय लिया गया और उसको संसद में भी लाया गया कि पीएसयूज की भागीदारी रहेगी, जिसमें हमें आर्थिक सहयोग मिलेगा। एफडीआई का निवेश, जहाँ तक एक्विपमेंट्स बनाने का संबंध है, इसी तरह एक फैसला करके 12

रिएक्टर एक ही निर्णय के द्वारा किए गए, which in itself is a history. कहने का तात्पर्य यह है और एक महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 50-60 वर्ष तक ये एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स देश के कुछ हिस्सों में सीमित थे, दक्षिण में अधिकतर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम में महाराष्ट्र। पहली बार इनको उत्तर भारत की तरफ एक्सपैंड किया गया है। दिल्ली राजधानी से ही लगभग 150 किलोमीटर दूर हरियाणा में गोरखपुर नाम के स्थान पर काम जारी है। दो-तीन वर्ष में वह फंक्शनल हो जाएगा।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): सर, मेरा सैकेंड सप्लीमेंट्री है कि परमाणु ऊर्जा नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक परपज को पूरा करने का भी साधन है। उदाहरण के लिए इस क्षेत्र में यूएसए ने अपने डोमिनेंस के कारण ग्लोबल न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को स्थापित करने में अहम रोल निभाया है। इसलिए परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा और जियो पॉलिटिक्स दोनों में इनवेस्टमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। स्पेस रिसर्च भी एक ऐसा डिपार्टमेंट है और भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन (इसरो) ने सैटेलाइट लॉन्च में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। इसरो ने करीब 30 देशों में 200 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसके साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकार्ड भी शामिल है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास अन्य देशों को परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए कैपिटल एंड एक्सपर्टीज से मदद करने की कोई योजना है ताकि इस क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र का जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज और डोमिनेंस है, वह बढ़ सके?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय 22 रिएक्टर फंक्शनल हैं और वर्तमान सरकार ने एक निर्णय लेते हुए 9 न्यूक्लियर पावर और 12 एडिशनल रिएक्टर 2024-25 तक लगाने का फैसला किया है। इसमें कुछ दूसरे देशों की कॉलेबोरेशन भी रहेगी और पाँच-पाँच भिन्न-भिन्न वेन्यूज पर ये लगाए जाएँगे। इसके अतिरिक्त जापान के साथ प्रधान मंत्री जी का जब दौरा था, एक अलग से एमओयू और उनके साथ एक समझौता साइन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि बड़ी मात्रा में और जैसा मैंने कहा कि अब एफडीआई के निवेश का रास्ता भी खोला गया, though in a

limited manner, in the sense that they cannot setup an atomic plant, but they can manufacture equipment and supply. निश्चय ही इसमें राशि उपलब्ध हो, बजट की दिक्कतें न हों और फॉरेन कॉलेबोरेशन हो। जहाँ तक आपने दूसरे देशों के कुछ एक उनके प्रावधान हैं, उनकी बात की। एक सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज ट्रीटी रहती है जो अंतर्राष्ट्रीय है। भारत उसका हिस्सा है और हमने उससे बढ़ कर एक कदम आगे जाकर एक इन्श्योरेंस पूल काम किया है, जिसका आपके पहले वाले प्रश्न से भी संबंध है और अंतर्राष्ट्रीय जो बाहर से हमारे साथ कॉलेबोरेशन होगी, उनको किसी प्रकार की शंका न रहे, उसको भी एड्रेस किया गया है। उसमें लगभग 2600 करोड़ रुपये की कॉम्पनसेशन का रहता है।

(1145/CS/RP)

अगर कोई हादसा या दुर्घटना हो जाए। अगर मैं बहुत आंकड़ों में जाऊँगा तो पहले 1200 फिर 1500 और यदि न हो तो चूँकि हम कम्पेन्सेटरी कन्वेन्शन के हस्ताक्षरकर्ता हैं, तो उसमें भी भारत इस समय निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा है।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज कैगा न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन के यूनिट 1 ने दिसम्बर, 2018 में लगातार 941 दिन चलकर ब्रिटेन के हैशम प्लांट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का और सभी वैज्ञानिकों का इस देश की तरफ से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही मैं यह बताता हूँ कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में कितने संबल हैं। अभी माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे तो मुझे 2011 की लोक सभा याद आ गई। उस समय गुजरात को केवल इसलिए सजा दी गई थी कि नेशनल प्रोग्राम सोलर एनर्जी बनाने से पहले आपने काम क्यों शुरू कर दिया, इसलिए आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी।

मेरा प्रश्न यह है कि थर्ड फेज में माननीय मंत्री जी ने यह फैसला किया था कि हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स की बात करेंगे और हम लोग थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स को बनाएंगे। यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स में आज भी हमें यूरेनियम के इम्पोर्ट की जरूरत पड़ती है। आज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में

विश्व न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से यही प्रश्न है कि थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स का भविष्य में देश का क्या प्रोग्राम है? न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी सबसे क्लीन टेक्नोलॉजी होगी और फिर हमें कोई इम्पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या इस पर हमारे देश ने काम करना शुरू किया है या नहीं?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदय, आदरणीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी और हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, जो इन्होंने 962 दिन के एक रिकॉर्ड का उल्लेख किया है। उसमें साथ में मैं यह भी जोड़ देता हूँ कि हमारा तारापुर का जो प्लांट महाराष्ट्र में है, उसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह भी विश्व में अपने में एक रिकॉर्ड है। विश्व में ऐसा बहुत कम बार होता है कि एक साल तक लगातार 365 दिन कोई रिएक्टर चलता रहे। हमारे यहाँ ऐसा 28 मर्तबा हो चुका है। इस दृष्टि से भी हमारा रिकॉर्ड रहा है।

जहाँ तक थोरियम का संबंध है, आदरणीय सदस्य का कहना ठीक है। We are one of the richest store houses of Thorium in the world and Thorium is going to be the main source of nuclear energy in the years to come. इसमें आरम्भ में कुछ दिक्कतें अवश्य थीं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ लगभग 12 मिलियन टन मोनोज़ाइट का रिजर्व है, क्योंकि यह मोनोज़ाइट से बनता है। We have planned that by the year 2031-32, there will be a ten-fold increase in the reserves. उसमें थोरियम का भी उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त थोरियम केवल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए नहीं, मैं एक बड़ी रोचक बात यह भी साझा करूँ कि थोरियम का इस्तेमाल नॉन एटॉमिक एप्लिकेशंस में भी होता है, जैसे हमारे बल्ब के फिलामेंट्स हैं, जैसे हमारी वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे हमारे लैम्प के फिलामेंट्स हैं। There are extra atomic applications of Thorium as well. दिक्कत इसमें केवल यह आई थी, पिछले तीन-चार वर्ष से पहले, 2012-13 के लगभग कि कुछ-कुछ तस्करी के समाचार आने लगे। Monazite is one of the associate minerals out of eight minerals which are found on the sand beaches of Kerala and Tamil Nadu. Granite is also one of them.

कुछ लोग ग्रेनाइट की खुदाई करने का कान्ट्रेक्ट लेते थे, साथ-साथ वे मोनोज़ाइट लेकर निकल जाते थे। अब उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। इमेजिंग से हमें पता चल जाता है। कहीं संदिग्ध मूवमेंट हो रही हो, तो उसका भी पता लगता है। जो हमारे चैक गेट्स हैं, चाहे रेडियो गेट्स हैं, उन्हें और ज्यादा सुदृढ़ कर लिया गया है। निश्चय ही थोरियम कार्यक्रम की तरफ बढ़त करने के लिए ये सारे प्रावधान किए जा रहे हैं।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Sir, I would like to put my question to the hon. Prime Minister. There is a major concern regarding storage of nuclear reactor waste, especially, in my State, in Kudankulam where a Russian Plant has been set up. The Government is planning to temporarily store the used fuel or the nuclear waste. That is the concern of the people of Tamil Nadu. Already, our people are scared of the nuclear plant being set up in Tamil Nadu. A severe protest was there. We have already seen three major nuclear plant disasters in the world. Moreover, storage of nuclear waste is an important concern. Is it possible for the Government to take the nuclear fuel or waste away from the reactors and store them in desert areas where there is no human presence? It would be safer.

(1150/RCP/RV)

DR. JITENDRA SINGH: I thank the hon. Member. He has raised a question which has been in discussion for quite some time because there were certain newspaper reports particularly in the newspapers published from Tamil Nadu. But, with all the confidence at my command, I would suggest that there is no apprehension as far as this is concerned. This is not specifically something which is happening only to Kudankulam Plant. The same process and the

same procedure is followed in the plants which are located in Rajasthan and in Maharashtra. Actually, if you allow me to just spend one minute into the scientific details, within the reactor itself, we have a storage system which is called In Reactor Wastage or IRW, something like that. So, whenever the reactor is in the process, the usable or used material – I would not say even waste because it might sometimes be again usable – is stored within a chamber which is a part of the reactor. It is stored there for a couple of days, weeks or months and not beyond that. It is because, if it is stored beyond that, what would happen is that more of the usable fuel which would come out will not have a space to get accommodated and, therefore, the reactor would become standstill. Therefore, after a couple of days, it is then shifted to, what is known as, Away from Reactor Waste (ARW). There, it is stored for almost 50 years. It is stored deep down, at least 30 metres below the surface of the earth, which is absolutely safe. This is the practice which is a standard practice followed all over the world, even in other plants in India. Somehow, some apprehension was raised because of some hearsay and it became a topic of discussion. But I would request the hon. Member, since he is a literate person, also to allay the fears about this and join us in making this awareness campaign more successful. Thank you.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब स्पीकर साहब, जम्मू-कश्मीर में बिजली की फ़राहमी की शदीद कमी है। इस हद तक कमी है कि कश्मीर डिवीजन में सब-ज़ीरो टेम्परेचर में दस से बारह घंटे की लोड शेडिंग होती है। आजकल जम्मू में, जहां 45 डिग्री सेल्सियस के आस-पास टेम्परेचर है, वहां भी दस से बारह घंटे की लोड शेडिंग होती है।

मैं आप की वसादत से जनाब वज़ीर मौसुफ़ से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार कब जम्मू-कश्मीर को उसके पावर प्रोजेक्ट्स वापस करने जा रही है, क्योंकि Jammu & Kashmir being a world renowned tourist destination, demand-supply deficit has an adverse fallout on the overall economy of the State. मैं समझता हूं कि मरक़ज़ी सरकार जम्मू-कश्मीर को उसके पावर प्रोजेक्ट्स को वापस देने के लिए वादहबन्द है, जो कि बड़े अर्से से सेन्टर की तहरीर में है। इसे कब तक वापस देने का इरादा है और क्या इसमें कोई शुरुआत हुई है?

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker, Sir, I welcome the question raised by the hon. Member. But please permit me to submit that this is actually related to the Ministry of Power and is not directly related to the Department of Atomic Energy. As far as the Department of Atomic Energy is concerned, I appreciate the first half of your concern that the increasing needs of energy are being felt even in peripheral States like Jammu & Kashmir and North East. What we have done in the last four-five years under the guidance of the Prime Minister is that we are trying to explore other venues where we could set up atomic plants. That is how we have come back to Haryana. We are already setting up a plant. We are in the process of exploring new sites in Punjab near Bathinda and near Patiala. We have a huge reserve in Meghalaya, in North East. But only because of landslides and some earthquake proneness, we got little held up. So, what I am trying to say is that as far as the atomic energy availability is concerned, we are gradually moving to different parts of the country. Possibly, one day, Jammu & Kashmir will also get that benefit.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Speaker, Sir for giving me an opportunity to ask a Supplementary Question. My Question is very specific. It would be in the notice of the hon. Minister that there is a nuclear atomic plant that has been proposed in the district of Srikakulam which is my very own district in the State of Andhra Pradesh. What is the status of this project? It has been under construction for a long time. I would like to know whether there are any bottlenecks, as such, or whether it is under a smooth progress. Thank you.

(1155/SMN/MY)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): I appreciate the hon. Member's concern. As of now, we have not come across any impediments or hurdles. But as I said, the process of setting up of a plant and making it functional goes through different stages. Since necessary checks and balances are also ensured from the safety point of view, it takes some time.

(ends)

(Q. 64)

SHRI KANUMURU RAGHURAMA KRISHNARAJU (NARSAPURAM): Thank you for giving me an opportunity to present a case which is related to my constituency and East and West Godavari districts of Andhra Pradesh.

It is with regard to the transport and marketing assistance in lieu of MEIS and other schemes that are available for export of agriculture products, and it is related to my area which is predominantly called as the rice bowl of India. It is also called the aquaculture hub of India. Seventy per cent of the sea food on the land is being exported from my Godavari districts. The removal of the MEIS Scheme and other schemes has caused a greatl concern. They are proposing transport incentive. For example, I would like to make a mention. For one container of sea food shrimps, they would be getting around Rs. 7 lakh by way of MEIS and the container transportation cost is around Rs. 2.5 lakh. Even if you give the entire transportation subsidy, still they would be losing around Rs. 3 lakh to Rs. 3.5 lakh on every container. Ultimately, the burden would fall on the aqua farmers. Already they are losing a lot and this would be a major burden.

In the same way, the transport subsidy for rice export would be pittance. It is hardly 20 per cent of what they were getting now. So, in view of the farmers' woes which are there in our area, I would request the hon. Minister to give a patient hearing as well and see that the farmers are not put to any greater loss.

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Speaker Sir, I think this has been one Government which over the last five years has been most responsive to anything to do with fisheries, to do with farmers and the very fact that we are supporting over 15 crore farmers and nearly one and a half crore fishermen in this country over the last five years with various schemes one after the other. It is testimony to our intention to support the community. I think the hon. Member has mixed up the transport subsidy to agricultural exports with the MEIS scheme. The MEIS has nothing to do with this particular scheme that is in reference in this question. The transport and marketing assistance scheme is a new scheme which we have introduced on 27th February, 2019 as recently as now. It is not in lieu of some other scheme. For the next one year, we are going to give support for providing assistance to the international component of freight and marketing of agricultural produce. We have a long list of products. This is going to be available in the Ministry. It has been carefully assessed as to what are the products that needs support and value-added products of fish and meat are covered under this policy. So, I think this is a benefit that the fishermen of Andhra Pradesh will also enjoy.

I must mention to the hon. Member that this is one Government which engages with the people. His request that we should give a patient hearing, I can assure him that our doors are always open. We welcome farmers, we welcome fishermen from Godavari to come and tell us as to how we can help them and what more we can do. For us, supporting the fishermen to do better

is the priority that we have started a new department which is focussed on fisheries and animal husbandry.

I am sure they will be happy to engage with your constituents from Godavari district to see how we can do better.

Hon. Speaker, before it becomes twelve, I would not get a chance. Since hon. Member has spoken about filibustering in an earlier question, I thought I must inform the House that filibustering is a political procedure where one or more Members of Parliament or Congress debate over a proposed piece of legislation so as to delay or entirely prevent that decision being made on the proposal. So, I know Mr. Tewari has fantastic knowledge of English. Many members do not even understand the words that he is mentioning. But I thought he must be educated about what filibustering is.

(ends)

QUESTION HOUR OVER